दिल्ली विकास प्राधिकरण
(बैठक कक्ष)

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार की प्रैस,
माया पुरी,
नई दिल्ली ।

प्राधिकार-पत्र

इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत किये गये नीचे लिखे कर्मचारी को प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दि॰वि॰प्रा॰ के पत्र संख्या-एफ॰ 1(2)2004/एसी/एमसी/डीडीए/75 दिनांक 4,अगस्त, 2004 के द्वारा भारत सरकार के राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की 20 प्रतियां सौंपने की कृपा करें, जिसके हस्ताक्षर नीचे सत्यापित किये गये हैं ।

27/8/04

(एस॰सी॰टुटेजा)
उप-निदेशक (बैठक कक्ष)

हस्ता/-
कर्मचारी का नाम: पदम सिंह
पद : अनुभाग
विभाग : बैठक कक्ष

सत्यापन(मुहर सहित)

कैलाश चन्द्र
KAILASH CHANDER
सहायक निदेशक (मिटिंग सैल)
Asstt. Director (Meeting Cell)
दि.वि.प्रा. / D.D.A.
विकास सदन, नई दिल्ली
Vikas Sadan,New Delhi

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926

No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926

No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926

No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2004/श्रावण 15, 1926
No. 693] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2004/SRAVANA 15, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

का.आ. 898(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी डी आई ए दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सज्जन कुमार और श्री किशन सिंह सांगवान सांसद (लोकसभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एम.सी./दि.वि.प्रा./75]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

S.O. 898(E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 2nd August, 2004 communicated that Shri Sajjan Kumar and Shri Kishan Singh Sangawan, Members of Lok Sabha have been elected to be members of the Advisory Council of Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2) 2004/AC/MC/DDA/75]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

2418 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926

No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926

No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि० सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926

No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 838(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/14/2004-डीडीआईए, दिनांक 16 जुलाई, 2004 द्वारा सूचित किया है कि श्री आर.के. आनन्द, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[फा. सं. 1(2)/2004/एसी/एम.सी/दिविप्रा/72]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 838(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 16th July, 2004 communicated that Shri R. K. Anand, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 1(2)/2004/AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.

2283 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-11011/5/2001-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 10th February 2004.

Office Order

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section(3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) the Central Government hereby appoints Shri Prabhash Singh, Engineer Member, DDA to hold the current duty charge of the post of Vice Chairman, DDA, with immediate effect, till the regular incumbent joins, vice Shri Anil Baijal.

(Parmjit Singh)
Desk Officer (DDIA)

Copy to: -

1. The Secretary to the Lt. Governor, Delhi
2. Chief Secretary, Government of NCT of Delhi
3. D/o Personnel & Training, North Block, New Delhi.
   Their OM No. 26/3/2004-EO(SM.II) dated 09.02.2004 refers.
4. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi.
5. Chairman, New Delhi Municipal Council.
6. Shri Prabhash Singh, Vice Chairman, DDA
7. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA
8. DG (W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi
9. PS to UDPAM.
10. Sr. PPS to Secretary (UD), MOUD
11. PS to AS(UD)/ JS (DL)/ JS (UD)/ JS(F)/ JS(II)

Desk Officer

No. K-13011/3/2000-DDIB.
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
(Delhi Division)
****

Nirman Bhavan, New Delhi-110011,
Dated the Feb.11 , 2004

प्रधान आयुक्त एवं सचिव कार्यालय
Pr. Commr. cum Secretary's Office
डायरी सं० Dy. No. 77-9
दिनांक Date 11/2/04

डि. वि. प्रा. / संसद ... शाखा
D.D.A. / PARLT. & ... BRANCH
डायरी सं. / DIARY No. 177
दिनांक / DATE 12/2/2004

A copy of Notification/ ~~Public Notice~~ dated 29th Jan, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

Encl; As above.

(S. Mukherjee)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy to:

1. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. the Commissioner (Planning) DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi with reference to their letter No. F3/96/98-MP-PTI/370 dated 8-9-03
3. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
4. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
5. The Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The DG(W), CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi
7. The Chief Planner, TCPO, vikas Bhavan, IP Estates, New Delhi
8. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi
9. The Information Officer, Ministry of Urban Development, New Delhi.

23-AD(MC)
12-2-04

Copy also to: PS to UDM/ Sr. PPS Secy. (UD)/ PS to JS(D&L)/PS to Director (DD).

Copies to EM, FM, CE (SEZ), CE(SWZ), CLM, CLD.
Also speak to me thereafter

AD(MC)

12/2/04 DD (P&Q) 11/2

Sh. AD(P&C)

12/2/04

Sh. A.K. Gupta

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2004/माघ 10, 1925
No. 121] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2004/MAGHA 10, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2004

का.आ. 149(अ).—यत: केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान/जोनल विकास योजना में कुछ उपांतरण करने का प्रस्ताव किया था, जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2002 की समसंख्यक सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार यह कहा गया था कि उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर इन उपांतरणों के संबंध में लिखित में आपत्तियां/सुझाव आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेजे जाएं।

2. यत: प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में सार्वजनिक सूचना के उत्तर में 1741 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए इंजीनियरिंग सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अत:, अब, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण

जोन "जे" में आने वाले महरौली-महिपालपुर रोड के दक्षिण में स्थित 56 हेक्टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन किया जाता है :

क्र.सं.	भूमि उपयोग का परिवर्तन		क्षेत्र	विवरण	
	से	को	(हेक्टेयर)		
1	2		3	4	
I	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	रिहायशी	14	37 हे.	उत्तर : महरौली-महिपालपुर रोड पूर्व : रीजनल पार्क/रिज दक्षिण : ग्रामीण उपयोग पश्चिम : ग्रामीण उपयोग
II	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	रिहायशी	23		पूर्वोत्तर : सेक्टर-डी, वसंत कुंज (पाकेट 6, 7 व 8) दक्षिण : ग्रामीण उपयोग पश्चिम : एअर इंडिया कालोनी

1	2		3	4	
III	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं	9	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	: महरौली-महिपालपुर रोड : स्पाइनल इंजुरीज हॉस्पिटल : सुलतान गढ़ी टॉम्ब : रिजनल पार्क/रिज
IV	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	मनोरंजनात्मक	10	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	: प्रस्तावित सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं : स्पाइनल इंजुरीज हॉस्पिटल : ग्रामीण उपयोग : रिजनल पार्क/रिज

[सं. के-13011/3/2000-डीडीआईबी]

एस. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2004

S.O. 149(E)— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India as Public Notice of even number dated the 18th September, 2002 by the Delhi Development Authority (DDA) in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions in writing to Commissioner-cum-Secretary, DDA as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas in response to the Public Notice, 1741 objections and suggestions were received with regard to the proposed modifications. A Committee was constituted by the DDA under Engineering Member, Delhi Development Authority to consider the objections/suggestions received with regard to the proposed modifications and gave recommendations to the Delhi Development Authority. The Authority has since submitted its recommendations to the Government and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan, 2001.

3. Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Sl. No.	Change of Land Use From	To	Area (Hect.)		Description	
I	Agricultural & Water Body — Rural	Residential	14	(37 Hect.)	NORTH EAST SOUTH WEST	: Mehrauli Mahipalpur Road : Regional Park/Ridge : Rural Use : Rural Use
II	Agricultural & Water Body — Rural	Residential	23		NORTH EAST SOUTH WEST	: : Sec. D. Vasant Kunj (Pkt. 6,7 & 8) : Rural Use : Air India Colony
III	Agricultural & Water Body — Rural	Public & Semi-Public Facilities	9		NORTH EAST SOUTH WEST	: Mehrauli Mahipalpur Road : Spinal Injuries Hospital : Sultan Garhi Tomb : Regional Park/Ridge
IV	Agricultural & Water Body — Rural	Recreational	10		NORTH EAST SOUTH WEST	: Proposed Public & Semi Public facilities : Spinal Injuries Hospital : Rural Use : Regional Park/Ridge

[No. K-13011/3/2000-DDIB]

S. MISHRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

No. F.1(Misc.)2004/MC/DDA/ 20 Dated: 12/2/04

Enclosed please find herewith a copy of letter No. K-13011/3/2000-DDIB dated 11.2.2004 received from Under Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation alongwith a copy of Notification dated 29.1.2004 for information and necessary action.

12/2/04

[S C TUTEJA]
Deputy Director [P&C]

1. Engineer Member
2. Finance Member
3. Chief Engineer [South East Zone]/(SWZ)
4. Commissioner [LM]
5. Commissioner [LD]

Encl.: As above.

No. K-13011/3/2000-DDIB.
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
(Delhi Division)
****

Nirman Bhavan, New Delhi-110011,
Dated the Feb.11, 2004

A copy of Notification/ ~~Public Notice~~ dated 29th Jan, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

Encl; As above.

(S. Mukherjee)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy to:

1. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. the Commissioner (Planning) DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi with reference to their letter No. F3/96/98-MP-PTI/370 dated 8-9-03
3. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
4. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
5. The Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The DG(W), CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi
7. The Chief Planner, TCPO, vikas Bhavan, IP Estates, New Delhi
8. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi
9. The Information Officer, Ministry of Urban Development, New Delhi.

Copy also to: PS to UDM/ Sr. PPS Secy. (UD)/ PS to JS(D&L)/PS to Director (DD).

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2004/माघ 10, 1925
No. 121] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2004/MAGHA 10, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2004

का.आ. 149(अ).—यत: केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान/जोनल विकास योजना में कुछ उपांतरण करने का प्रस्ताव किया था, जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2002 की समसंख्यक सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार यह कहा गया था कि उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर इन उपांतरणों के संबंध में लिखित में आपत्तियां/सुझाव आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेजे जाएं।

2. यत: प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में सार्वजनिक सूचना के उत्तर में 1741 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए इंजीनियरिंग सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अत:, अब, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण

जोन "जे" में आने वाले महरौली-महिपालपुर रोड के दक्षिण में स्थित 56 हेक्टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन किया जाता है :

क्र.सं.	भूमि उपयोग का परिवर्तन से	को	क्षेत्र (हेक्टेयर)		विवरण	
1	2		3		4	
I	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	रिहायशी	14	37 हे.	उत्तर	: महरौली-महिपालपुर रोड
					पूर्व	: रीजनल पार्क/रिज
					दक्षिण	: ग्रामीण उपयोग
					पश्चिम	: ग्रामीण उपयोग
II	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	रिहायशी	23		पूर्वोत्तर	: सेक्टर-डी, वसंत कुंज (पाकेट 6, 7 व 8)
					दक्षिण	: ग्रामीण उपयोग
					पश्चिम	: एअर इंडिया कालोनी

1	2		3	4	
III	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं	9	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	: महरौली-महिपालपुर रोड : स्पाइनल इंजुरीज हॉस्पिटल : सुलतान गढ़ी टॉम्ब : रिजनल पार्क/रिज
IV	कृषि व जल निकाय-ग्रामीण	मनोरंजनात्मक	10	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	: प्रस्तावित सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं : स्पाइनल इंजुरीज हॉस्पिटल : ग्रामीण उपयोग : रिजनल पार्क/रिज

[सं. के-13011/3/2000-डीडीआईबी]

एस. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2004

S.O. 149(E)— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India as Public Notice of even number dated the 18th September, 2002 by the Delhi Development Authority (DDA) in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions in writing to Commissioner-cum-Secretary, DDA as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas in response to the Public Notice, 1741 objections and suggestions were received with regard to the proposed modifications. A Committee was constituted by the DDA under Engineering Member, Delhi Development Authority to consider the objections/suggestions received with regard to the proposed modifications and gave recommendations to the Delhi Development Authority. The Authority has since submitted its recommendations to the Government and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan, 2001.

3. Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Sl. No.	Change of Land Use From	To	Area (Hect.)		Description	
I	Agricultural & Water Body — Rural	Residential	14	(37 Hect.)	NORTH EAST SOUTH WEST	: Mehrauli Mahipalpur Road : Regional Park/Ridge : Rural Use : Rural Use
II	Agricultural & Water Body — Rural	Residential	23		NORTH EAST SOUTH WEST	: : Sec. D. Vasant Kunj (Pkt. 6,7 & 8) : Rural Use : Air India Colony
III	Agricultural & Water Body — Rural	Public & Semi-Public Facilities	9		NORTH EAST SOUTH WEST	: Mehrauli Mahipalpur Road : Spinal Injuries Hospital : Sultan Garhi Tomb : Regional Park/Ridge
IV	Agricultural & Water Body — Rural	Recreational	10		NORTH EAST SOUTH WEST	: Proposed Public & Semi Public facilities : Spinal Injuries Hospital : Rural Use : Regional Park/Ridge

[No. K-13011/3/2000-DDIB]

S. MISHRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

90-G-PCS
20/2/04

No. K- 12016/6/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 19th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Insertion of a Chapter on Conservation of Heritage Building and precincts

A copy of Notification dated 9th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

दि. वि. प्रा. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARL. & CO-ORDN. BRANCH
डायरी सं. / DIARY No. 198
दिनांक / DATE 20/2/2004

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

29-AD MC 23-2-04

Copies to CE(G), CA, Dir (LS), Lib Officer, DC(R)

DD(PRE) 20/2

20/2/04

Delhi Development Authority (Meeting Cell)
No. F.2(Misc)2004/MC/24 Dt. 23/2/04
Copy forwarded to Comm(Plg), Chief Arch., Dir(LS), Lib Officer, Dir(PR) for information

AD(MC)/24

23/2/04 Dir(PR)

2 LO 23/2/04

23/2/04

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2004/माघ 23, 1925
No. 157] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2004/MAGHA 23, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2004

का.आ. 188(अ).— यतः कुछ उपांतरण/परिवर्द्धन, जिन्हें केन्द्र सरकार दिल्ली में हेरीटेज भवनों की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल करने के लिए दिल्ली भवन निर्माण उप-नियम, 1983 में करने का प्रस्ताव करती है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 की समसंख्यक सार्वजनिक अधिसूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/ सुझाव उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे ।

2. यतः सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में कोई आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली भवन निर्माण उप नियमों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उपांतरण

भवन निर्माण उप नियम 1983 में खंड 23 जोड़ा जाता है जो इस प्रकार है :-

23. हेरीटेज भवनों/ हेरीटेज परिवेश तथा प्राकृतिक क्षेत्र सहित हेरीटेज स्थलों का संरक्षण

हेरीटेज स्थलों के संरक्षण में ऐतिहासिक सौंदर्य, वास्तुशिल्प, सांस्कृतिक अथवा पर्यावरण की

दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन, कलाकृतियां, संरचनायें, क्षेत्र तथा परिवेश (हेरीटेज भवन व हेरीटेज परिवेश), पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र अथवा रमणीय स्थल शामिल हैं ।

23.1 प्रयोज्यता

ये विनियम हेरीटेज स्थलों के लिए लागू होंगे, जिनमें ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सौंदर्य, सांस्कृतिक अथवा पर्यावरणीय महत्व के भवन, कलाकृतियां, संरचनायें, सड़कें तथा परिदृश्य शामिल होंगे (जिन्हें इसके बाद सूचीबद्ध हेरीटेज भवन/सूचीबद्ध हेरीटेज परिदृश्य) कहा जाएगा और पर्यावरणीय महत्व अथवा रमणीय प्राकृतिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (ओं) में/मास्टर प्लान में चुने गये पवित्र उपवन, पहाड़, पहाड़ियों, जलाशय (और उनके आस पास का क्षेत्र), खुले क्षेत्र, वन क्षेत्र, विशेष स्थल, रास्ते, पगडंडियां, अश्वमार्ग (जिन्हें इसके बाद "सूचीबद्ध प्राकृतिक क्षेत्र " कहा जाएगा) शामिल हैं ।

23.1.1 परिभाषायें

(क) "हेरीटेज भवन " में एक या अधिक अहाते वाले भवन अथवा उसका कोई हिस्सा तथा/अथवा ढांचा तथा/अथवा कलाकृति शामिल हैं, जिसे ऐतिहासिक तथा/अथवा वास्तुशिल्प तथा/अथवा कला तथा/अथवा सौंदर्य तथा/अथवा सांस्कृतिक तथा/अथवा पर्यावरणीय तथा/अथवा पारिस्थितिकी प्रयोजने के लिए संरक्षित तथा/अथवा सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है और इसमें ऐसे भवन अथवा उसके हिस्से के आस पास का भूखंड शामिल है जिसकी उस भवन के ऐतिहासिक तथा/अथवा वास्तुशिल्प तथा/अथवा सौंदर्य तथा/अथवा सांस्कृतिक मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए घेराबंदी अथवा ढकना अपेक्षित है ।

(ख) "हेरीटेज परिसर " का अर्थ है और उसमें शामिल है कोई भी ऐसा स्थान जिसका ऐतिहासिक और/अथवा वास्तुशिल्पिय और /अथवा सौंदर्यीकरण और/अथवा सांस्कृतिक और/अथवा पर्यावरणीय और/अथवा पारिस्थितिकीय प्रयोजन से संरक्षण और/अथवा परिरक्षण करना अपेक्षित है । इस प्रकार के स्थल की घेराबंदी दीवारों अथवा किसी क्षेत्र-विशेष अथवा स्थान अथवा भवन की चारदीवारियों अथवा उसके आस पास एक अधिकल्पित रेखा के द्वारा की जानी चाहिए ।

(ग) "संरक्षण" का अर्थ है किसी स्थान की देखरेख संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया जिससे उसका ऐतिहासिक और/अथवा वास्तुशिल्पीय और/अथवा सौंदर्यीकरण संबंधी और/अथवा सांस्कृतिक महत्व बनाये रखा जा सके तथा जिसमें रखरखाव, परिरक्षण, पुनरूद्धार, पुनर्निर्माण और इनमें से एक से अधिक को अपनाया जाना अथवा मिलाना शामिल है ।

(घ) "परिरक्षण" का अर्थ है और इसमें शामिल है किसी स्थान की संरचना की मौजूदा स्थिति को बनाये रखना तथा उसके ह्रास में रोक लगाना ।

(ड.) "पुनरूद्धार" का अर्थ है और इसमें शामिल है अतिरिक्त ढांचे हटाकर अथवा उसके मौजूदा अवयवों को नयी सामग्री का उपयोग किये बिना उसकी पुनर्संज्जा करके किसी स्थल की मौजूदा संरचना को जहां तक संभव हो सके पूर्वावस्था में लाना ।

(च) "पुनर्निर्माण" का अर्थ है और इसमें शामिल है किसी स्थल को जहां तक संभव हो पूर्वावस्था में लाना तथा उसकी संरचना में नयी अथवा पुरानी सामग्री का उपयोग करना । इसमें पुनर्सृजन अथवा आनुमानिक पुनर्निर्माण दोनों ही शामिल नहीं है ।

23.2 हेरीटेज भवनों के मालिकों का दायित्वः

हेरीटेज भवनों तथा हेरीटेज परिवेशों या हेरीटेज गलियों में स्थित भवनों के मालिकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव नियमित रूप से करायें । सरकार, दिल्ली नगर निगम या स्थानीय निकाय तथा संबंधित प्राधिकरण, सरकार, दिल्ली नगर निगम या अन्य स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाले भवनों को छोड़कर किसी अन्य भवन की ऐसी मरम्मत या रखरखाव के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे ।

23.3 विकास/पुनर्विकास/मरम्मत इत्यादि पर प्रतिबंध

(i) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, नयी दिल्ली नगर परिषद की पूर्वानुमति के बिना उक्त सूचीबद्ध भवनों या सूचीबद्ध परिवेश या सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों के किसी भाग के विकास या पुनर्विकास या उनमें इंजीनियरिंग कार्य या परवर्द्धन/परिवर्तन, मरम्मत, भवन के रंगरोगन सहित नवीकरण, विशिष्ट विशेषताओं में बदलाव या प्लास्टर करने

या गिराने की अनुमति नहीं दी जाएगी । ऐसी अनुमति देने के पहले संबंधित एजेंसी सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली हेरीटेज संरक्षण समिति से परामर्श करेगी तथा हेरीटेज संरक्षण समिति के परामर्श के अनुसार कार्य करेगी ।

(ii) यह भी कि सूचीबद्ध भवनों (सूचीबद्ध गलियों या परिवेशों के अन्दर के भवनों) को गिराने या वृहत परिवर्द्धन/परिवर्तन करने, या किसी सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र में निर्माण करने, या किसी सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र की चहारदीवारी में परिवर्तन करने की कोई अनुमति देने से पहले जनता से आपत्तियों एवं सुझाव मांगे जायेंगे तथा उनपर हेरीटेज संरक्षण समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(iii) यह भी कि केवल अपवादिक मामलों में, जिनके कारण रिकार्ड में दर्ज किये जायेंगे, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद इस मामले को पुनर्विचार के लिए हेरीटेज संरक्षण समिति को वापस भेज सकते हैं ।

तथापि, ऐसे पुनर्विचार के बाद हेरीटेज संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

23.4 शास्तियां

इन विनियमों का उल्लंघन अनधिकृत विकास संबंधी प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा । हेरीटेज भवनों एवं हेरीटेज परिवेशे की जानबूझकर अवहेलना करने तथा/या उन्हें नुकसान पहुंचाने के प्रमाणित होने के मामले में या यदि अवहेलना या किसी अन्य वजह से भवन को नुकसान पहुंचाने या ध्वस्त करने की अनुमति दी जाती है तो संबंधित अधिनियम के तहत प्रावधान की गयी दांडिक कार्रवाई के अतिरिक्त उस स्थल पर किसी नये भवन के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि आयुक्त, दिल्ली नगर निगम/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की समुचित अनुमति के बिना किसी हेरीटेज भवन या हेरीटेज परिवेश में स्थित किसी भवन को नुकसान पहुंचाया जाता है या ध्वस्त किया जाता है ।

अनधिकृत रूप से गिराये गये या नुकसान पहुंचाये गये किसी हेरीटेज भवन को पुनः बनाने/के पुनर्निर्माण के अनुरोध पर विचार करने के लिए हेरीटेज संरक्षण समिति स्वतंत्र होगी, बशर्ते विनिर्दिष्ट अन्य निग्रहों के अतिरिक्त ऐसे नये निर्माण के सभी तलों का सम्मिलित कुल निर्मित क्षेत्र मूल हेरीटेज भवन के सभी तलों के सम्मिलित कुल निर्मित क्षेत्र से उसी स्वरूप या शैली में अधिक न हो ।

23.5 हेरीटेज भवन, हेरीटेज परिवेश तथा सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र सहित हेरीटेज स्थलों की सूची तैयार करना

हेरीटेज भवनों, हेरीटेज परिवेशों सहित हेरीटेज स्थलों तथा सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों की सूची हेरीटेज संरक्षण समिति की सलाह से दिल्ली नगर निगम के आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा तैयार तथा पूरी की जानी है । इसे अंतिम रूप दिये जाने से पहले जनता की आपत्तियां तथा सुझाव मांगे जाने हैं तथा उनपर विचार किया जाना है । उपर्युक्त सूची,जिसपर यह विनियमन लागू होगा, भवन उपनियमों के उद्देश्य के लिए इस विनियमन का हिस्सा नहीं बनेगी । इस सूची को समय-समय पर सरकार द्वारा संबंधित एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर या स्वतः प्रेरणा से बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि सूची में कुछ जोड़ने से पहले जनता से आपत्तिया तथा सुझाव मांगे जायें तथा उनपर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/ नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष तथा/या सरकार तथा/या हेरीटेज संरक्षण समिति द्वारा विधिवत विचार किया जाए ।

जब एक भवन या भवन समूह या प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जाए तो इसका अभिप्रायः स्वतः यह होगा (जब तक कि कुछ अन्य बातें न लिखी गयी हों) कि परिसर/प्लाट की चहारदीवारी के भीतर की सभी अनुषंगी संरचनाओं तथा बनावटी चीजों इत्यादि के साथ-साथ संपूर्ण परिसर/प्लाट की चहारदीवारी सहित पूरी संपत्ति सूची का हिस्सा बनेगी ।

23.6 विकास मानकों में परिवर्तन/संशोधन/छूट

सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली उक्त हेरीटेज संरक्षण समिति की सलाह पर तथा लिखित रूप में कारण रिकार्ड किये जाने पर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नयी दिल्ली नगर पालिका परिसर के अध्यक्ष किसी हेरीटेज स्थल की ऐतिहासिक या सौंदर्यपरक या सांस्कृतिक या वास्तुशिल्पीय या पर्यावरणीय विशेषता के परिरक्षण या संरक्षण या उसे बरकरार रखने के लिए, यदि आवश्यकता हो, दिल्ली मास्टर प्लान में प्रावधान किये गये विकास नियंत्रक मानकों या दिल्ली के भवन उपनियमों में परिवर्तन, संशोधन करने या छूट देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अनुसार प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

23.7 हेरीटेज परिवेश/प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र

इस भवन उप नियम सं0 23.3 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित गलियों (स्ट्रीट), परिवेशों, क्षेत्रों तथा (जहां हेरीटेज संरक्षण समिति द्वारा आवश्यक समझा जाये) प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों के मामले में विकास की अनुमति संबंधित गलियों, परिवेशों/प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित विशेष पृथक विनियम, जो हेरीटेज संरक्षण समिति के परामर्श से दिल्ली नगर निगम के आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा बनायें जायेंगे, के अनुसार दी जाएगी ।

परिवेशों, गलियों, प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों के लिए विशेष पृथक विनियमों को अंतिम रूप दिये जाने से पहले उनका ड्राफ्ट जनता से आपत्तियों तथा सुझाव प्राप्त करने के लिए सरकारी राजपत्र तथा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित

किया जाएगा । सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष/हेरीटेज संरक्षण समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

उपर्युक्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात हेरीटेज संरक्षण समिति के परामर्श से संबंधित एजेंसी गलियों, परिवेशों, क्षेत्रों तथा प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों के लिए पृथक विनियमों के उपर्युक्त ड्राफ्ट को संशोधित (यदि आवश्यक हो) करेगा तथा उन्हें अधिसूचित करने के लिए सरकार को अग्रेषित करेगी ।

23.8 सड़क चौड़ी करना

दिल्ली मास्टर प्लान/क्षेत्रीय विकास योजना या भू-विन्यास (ले आऊट) योजना के तहत मौजूदा सड़कों के चौड़ाकरण, मौजूदा हेरीटेज भवनों (यद्यपि वे हेरीटेज परिवेश में शामिल नहीं भी किये गये हों) या जो सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, पर विचार करते हुए किया जाएगा ।

23.09 हैरिटेज भवनों का लाभकारी उपयोग

हैरिटेज संरक्षण सूची में शामिल गैर-वाणिज्यिक उपयोग जोनों में स्थित भवनों के मामले में यदि स्वामी सूचीबद्ध हैरिटेज भवन को मौजूदा स्थिति में रखने को सहमत हों और आवश्यक मरम्मत के साथ उसकी हैरिटेज को संरक्षित करने को सहमत हो और स्वामी/स्वामियों/पट्टाधारियों द्वारा इस आशय की लिखित वचनबद्धता दी जाती है तो स्वामी/स्वामियों/पट्टाधारियों को हैरिटेज संरक्षण समिति के अनुमोदन से अनुमत्य उपयोग जोन के भीतर ही ऐसे हैरिटेज भवन के भीतर गैर वाणिज्यिक/कार्यालय उपयोग/होटल उपयोग में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है । बशर्ते यदि विरासती भवन का उपयुक्त ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता अथवा भवन के हैरिटेज महत्व के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ की जाती है तो वाणिज्यिक/कार्यालय/होटल उपयोग की अनुमति नहीं होगी ।

23.10 रूपरेखा और वास्तुकीय शौन्दर्य को बनाए रखना

दिशानिर्देशों के बनने के बाद हैरिटेज स्थलों के हैरिटेज क्षेत्र अथवा परिवेश के भीतर भवन में क्षेत्र की रूपरेखा को बनाए रखा जाएगा और समीपवर्ती क्षेत्र में मौजूदा वास्तुकीय शैली(ऊंचे या बहुमंजिले भवन विकसित किए बिना) का अनुसरण किया जाएगा ताकि उन विरासत स्थलों का महत्व व शौन्दर्य या दृश्य कम या समाप्त न होने पाए । विरासत स्थलों के क्षेत्र के भीतर या परिवेश में विकास , हैरिटेज संरक्षण समिति के परामर्श से या डीडीए/एनडीएमसी/एमसीडी द्वारा संबंधित जोनों के लिए निर्धारित अलग विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो के अनुसार आयुक्त, दिल्ली नगर निगम/उपाध्यक्ष, डीडीए/अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

23.11 प्रतिबंधित प्रसंविदा

इस अधिसूचना की तारीख को सरकार या दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा लीजहोल्ड प्लाटों पर प्रसंविदा , निबंधन व शर्तों के अंतर्गत लगाए गए मौजूदा प्रतिबंध विकास नियंत्रण विनियमों के साथ-साथ लगाए जाने जारी रहेंगे । तथापि, हैरिटेज परिरक्षण हित/पर्यावरणीय संरक्षण में कोई विवाद होने पर यह विरासत विनियम लागू रहेगा ।

23.12 सूचीबद्ध भवनों/सूचीबद्ध क्षेत्रों की ग्रेडिंग

सूचीबद्ध भवनों/सूचीबद्ध हैरिटेज क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा । इनकी परिभाषा और विकास अनुमति हेतु बुनियादी दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :-

सूचीकरण से स्वामित्व या उपयोग परिवर्तन नहीं रुकता । तथापि, हैरिटेज संरक्षण समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे सूचीबद्ध हैरिटेज भवन/सूचीबद्ध क्षेत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती इस सूचीबद्ध हैरिटेज स्थल के सौंदर्य के अनुरूप उपयोग होना चाहिए ।

ग्रेड-I	ग्रेड-II	ग्रेड-III
(क) परिभाषा हेरिटेज ग्रेड-I में राष्ट्रीय अथवा ऐतिहासिक महत्व के भवन और क्षेत्र शामिल हैं जो उत्कृष्ट वास्तुकीय शैली, डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा सामग्री उपयोग वाले हों और/ या सौन्दर्यपरक हों ; उन्हें एक महान एतिहासिक घटना, व्यक्तित्व , आंदोलन या संस्थान के साथ जोड़ा जाए । उनका संबंध क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक घटना से हो । सभी प्राकृतिक स्थल ग्रेड-I में आएंगे ।	हेरिटेज ग्रेड-II (क और ख) में विशेष वास्तुकीय अथवा सौन्दर्यपरक गुण अथवा सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के भवन और क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन हेरिटेज ग्रेड-I में निम्न श्रेणी के होते हैं । वे स्थानीय ऐतिहासिक घटना से संबंधित होते हैं, जो क्षेत्र की प्रतिष्ठा और पहचान में योगदान देते हैं । वे कुशल कारीगर की कारीगरी हों अथवा सादृश्य और प्रदर्शनकारी प्रतिकृति हो अथवा किसी विशेष जलवायु के अनुकूल डिजाइन की गई हो ।	हेरिटेज ग्रेड-III में टाउनस्केप के महत्व के भवन और क्षेत्र शामिल हैं ; जो वास्तुकीय, सौन्दर्यपरक अथवा सामाजिक हित वाले हो लेकिन हेरिटेज ग्रेड-II में नहीं हो । वे उस स्थान की विशेषता से अवगत कराते हैं तथा एक समुदाय अथवा क्षेत्र विशेष की जीवनशैली का प्रतिनिधित्व कर सकें तथा साथ ही अपने प्रतिवेश अथवा दृश्य के विशेष गुण और ऊंचाई, चौड़ाई व माप की समानता से पहचाने जा सकें ।
(ख) उद्देश्य हेरिटेज ग्रेड-I में पूर्ण सावधानी पूर्वक परिरक्षण अपेक्षित है ।	हेरिटेज ग्रेड-II में बुद्धिमानीपूर्वक संरक्षण अपेक्षित है ।	हेरिटेज ग्रेड-II में बुद्धिमानीपूर्वक संरक्षण अपेक्षित है (लेकिन ग्रेड-II से कम पैमाने पर तथा अद्वितीय आकृतियों व प्रतीकों का विशेष संरक्षण) ।
(ग) परिवर्तनों का दायरा हेरिटेज भवनों अथवा प्राकृतिक आकृतियों में कोई बाहरी अथवा आंतरिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाए जब तक कि भवनों/ अथवा क्षेत्रों अथवा उनके किसी हिस्से या आकृति की मजबूती तथा उनका जीवन काल बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो । इस प्रयोजनार्थ, बिल्कुल ही आवश्यक और न्यूनतम परिवर्तनों की अनुमति नही होगी और ऐसा मूल ढांचे के अनुरूप होना चाहिए ।	ग्रेड-II (क) आन्तरिक परिवर्तनों और अनुकूलतम पुनः उपयोग करने की अनुमति दी जाए लेकिन गहन जांच पड़ताल के बाद सभी विशिष्ट पहलुओं का संरक्षण सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा , जिनके लिए इसे हेरिटेज ग्रेड-II में शामिल किया गया है । ग्रेड-II (ख) : उपर्युक्त के अलावा, उसी प्लाट अथवा परिसर में विस्तार अथवा अतिरिक्त निर्माण करने की अनुमति विशेष परिस्थितियों में दी जा सकेगी, बशर्ते विस्तार/ अतिरिक्त निर्माण, मौजूदा हेरिटेज भवनों, अथवा क्षेत्रों के अनुरूप ऊंचाई व दृश्य के अनुसार हो ।	आंतरिक परिवर्तनों और उनका अनुकूलतम पुनः उपयोग करने की अनुमति दी जाए । परिवर्तनों में उसी प्लाट अथवा परिसर में विस्तार और अतिरिक्त निर्माण शामिल हो सकता है । तथापि, कोई भी परिवर्तन उसके सौन्दर्य के अनुरूप हो और इस प्रकार हो कि इससे मौजूदा हेरिटेज भवन/ क्षेत्र का आकर्षण कम न हो ।

(घ) प्रक्रिया: परिवर्तनों के लिए विकास अनुमति हेरिटेज संरक्षण समिति को परामर्श करके दी जाएगी ।	परिवर्तनों के लिए विकास अनुमति हेरिटेज संरक्षण समिति से परामर्श करके दी जाएगी ।	परिवर्तनों के लिए विकास अनुमति हेरिटेज संरक्षण समिति से परामर्श करके दी जाएगी ।
(ड.) परिदृश्य/आस-पास के क्षेत्र का विकास: हेरिटेज ग्रेड-I के आस-पास के क्षेत्र का सारा विकास विनियमित तथा नियंत्रित होगा ताकि इससे हेरिटेज ग्रेड-I की भव्यता अथवा वहाँ का परिदृश्य प्रभावित न हो ।	हेरिटेज ग्रेड-II के आस-पास के क्षेत्र का सारा विकास विनियमित तथा नियंत्रित होगा ताकि इससे हेरिटेज ग्रेड-II की भव्यता अथवा वहाँ का परिदृश्य प्रभावित न हो ।	हेरिटेज ग्रेड-III के आस-पास का सारा विकास विनियमित तथा नियंत्रित होगा ताकि इससे हेरिटेज ग्रेड-III की भव्यता अथवा वहाँ का परिदृश्य प्रभावित न हो ।

23.13 उल्लिखित किसी भी बात से प्लॉट के स्वामी/कब्जेधारक को किसी हेरिटेज परिसर अथवा प्राकृतिक हेरिटेज स्थल में स्थित अपने हेरिटेज भवन/भवनों को गिराने, पुनर्निर्मित करने अथवा उनमें परिवर्तन करने का हक नहीं मिलता है, यदि हेरिटेज संरक्षण समिति की राय में इस प्रकार से गिराया जाना/पुनर्निर्माण/परिवर्तन अवांछनीय हो ।

23.14 हेरिटेज संरक्षण समिति को, विशेषकर उनके द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, यह निदेश देने का अधिकार होगा कि क्षेत्र विशेष के सौंदर्य के संरक्षण के लिए भवनों की बाह्य डिज़ाइन और ऊँचाई के संबंध में उनसे अनुमोदन लिया जाना चाहिये ।

23.15 हेरिटेज स्थलों में संकेत-चिन्ह और सड़कों की साज-सज्जा सहित बाहरी प्रदर्शनी संरचनाएं

दिल्ली नगर निगम आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष की सलाह पर हेरिटेज संरक्षण समिति हेरिटेज स्थलों में संकेत चिन्हों, बाहरी प्रदर्शनी संरचनाओं और सड़कों की साज-सज्जा के विनियमन के लिए विनियम अथवा दिशानिर्देश तैयार करेगी ।

23.16 हेरिटेज संरक्षण समिति का गठन

हेरिटेज संरक्षण समिति सरकार द्वारा नियुक्त की जाएगी जिसका गठन निम्नानुसार होगा:

(i) अपर सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय — अध्यक्ष

(ii) अपर महानिदेशक (वास्तुशिल्प), के.लो.नि.वि. — सदस्य

(iii) संरचनात्मक इंजीनियर जिसके पास फील्ड में दस वर्षों का अनुभव और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, भारत की सदस्यता हो — सदस्य

वास्तुकार जिसके पास 10 वर्षों का अनुभव हो

(क) शहरी डिज़ाइनर — सदस्य

(ख) संरक्षण वास्तुकार — सदस्य

(iv) पर्यावरणविद् जिसे विषय की गहन जानकारी हो और 10 वर्षों का अनुभव हो — सदस्य

(v) इतिहासकार जिसे क्षेत्र के बारे में जानकारी हो और फील्ड में 10 वर्षों का अनुभव हो — सदस्य

(vi) प्राकृतिक इतिहासकार जिसे फील्ड में 10 वर्षों का अनुभव हो — सदस्य

(vii) मुख्य नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन संगठन — सदस्य

(viii) मुख्य नगर नियोजक, दिल्ली नगर निगम — सदस्य

(ix) आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण — सदस्य

(x) मुख्य वास्तुकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् — सदस्य

(xi) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के प्रतिनिधि — सदस्य

(xii) सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग — सदस्य-सचिव

(क) समिति को तीन अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा जो अपेक्षित अनुभव रखते हों ।

(ख) अध्यक्ष तथा सरकारी विभाग/स्थानीय निकायों से इतर सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

समिति के विचारार्थ विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित होंगे:-

(i) दिल्ली नगर निगम के आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को भवन निर्माण उप नियम सं0 23.3 के तहत विकास की अनुमति और अनुमति की शर्तों के संबंध में परामर्श देना (भवन उपनियम सं0 23 के तहत)

(ii) हेरिटेज़ स्थलों की अनुपूरक सूची तैयार करना, जिसमें भवन कलाकृतियाँ, संरचनाएं, सड़कें, क्षेत्र, ऐतिहासिक, सौंदर्यपरक, वास्तुशिल्पीय, सांस्कृतिक अथवा अपर्यावरणीय महत्व के परिसर तथा पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों, परिदृश्य सौंदर्य, जिसमें पवित्र उपवन, पहाड़-पहाड़ियाँ, जलाशय (और उसके आस-पास के क्षेत्र), खुले क्षेत्र, वन क्षेत्र, विशेष स्थल, रास्ते, पगडंडियां, अश्व मार्ग इत्यादि शामिल हैं, उनकी अनुपूरक सूची तैयार करना, जिन पर यह भवन निर्माण उप-नियम लागू होगा ।

(iii) क्या भवन निर्माण उप-नियमों में किसी छूट, संशोधन, परिवर्तन करने अथवा विसंगति दूर करने की आवश्यकता है, इस बारे में परामर्श देना ।

(iv) परिसरों और आवश्यकता होने पर प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए विशेष विनियम/दिशानिर्देश तैयार करना और इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को परामर्श देना ।

(v) यह परामर्श देना कि विनिर्दिष्ट क्षेत्रों (क्षेत्रों के नाम दें) में वाणिज्यिक/कार्यालयी/होटलों से संबंधित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है या नहीं तथा यह अनुमति किस स्थिति में खारिज़ की जाएगी ।

(vi) दिल्ली नगर निगम आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को इस भवन निर्माण उप-नियम के तहत बाहरी विज्ञापनों/बिलबोर्डों/स्ट्रीट फर्नीचर के संबंध में विनियमन करने अथवा इन्हें हटाने/लगाने के बारे में परामर्श देना ।

(vii) हेरिटेज स्थलों के सौंदर्यीकरण की स्कीमें प्रायोजित करने वाले निजी दलों अथवा सार्वजनिक/सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में दिल्ली नगर निगम आयुक्त/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को परामर्श देना ।

(viii) सूचीबद्ध भवनों के लिए विशेष डिज़ाइनें और दिशानिर्देश/विवरणिकाएं तैयार करना । भवनों की ऊंचाई और अन्य महत्वपूर्ण बाहरी विशेषताओं जैसे विशेष प्रकार की बालकनियों और अन्य हेरिटेज मदों के रख-रखाव के संबंध में विनियमन करना तथा प्रतिस्थापन करते समय जहाँ तक संभव हो सके पुरानी संरचना को अक्षुण्ण रखते हुए उपयुक्त सामग्री अपनाते हुए उचित डिजाइन का सुझाव देना ।

(ix) अपनाए जाने वाले डिजाइन घटकों और संरक्षण सिद्धांतों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करना तथा इस विनियमन के प्रयोजन के लिए अन्य दिशानिर्देश तैयार करना ।

(x) विकास अनुमतियों की जांच के दौरान समय-समय पर यथा अपेक्षित किसी भी अन्य मुद्दे पर और हेरिटेज /संरक्षण के समग्र हित में आयुक्त, दिल्ली नगर निगम/ उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण/ अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को सलाह देना ।

(xi) सूचीबद्ध भवनों/ विरासती भवनों और सूचीबद्ध परिवेशों/ विरासती परिवेशों और सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों के मामले में डीडीए /एमसीडी/एनडीएमसी एक्ट के तहत अपीलों के मामले में स्वतंत्र रूप से अथवा माध्यम से अथवा आयुक्त, दिल्ली नगर निगम/ उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण/ अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की और से सरकार के समक्ष प्रस्तुत होना ।

23.17 हेरिटेज भवन के रूप में सूचीबद्ध होने के परिणाम :

विनियमन, हेरिटेज भवनों को गिराने अथवा उनमें परिवर्तन करने को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करते । इसमें एकमात्र अपेक्षा यह होती है कि हेरिटेज दृष्टिकोण से आयुक्त, दिल्ली नगर निगम/ उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण/ अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा हेरिटेज संरक्षण समिति से स्वीकृति ले ली जाए ।

23.18 स्वामित्व अप्रभावित :

हेरिटेज भवनों की बिक्री और खरीद के लिए दिल्ली नगर निगम/ दिल्ली विकास प्राधिकरण / नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अथवा हेरिटेज संरक्षण समिति से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है । विनियमनों से स्वामित्व और उपयोग प्रभावित नहीं होता है । तथापि, ऐसा उपयोग उक्त सूचीबद्ध परिवेशों/ भवनों के अनुकूल होना चाहिए । यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि इन भवनों से संबंधित विकास अनुमति 60 दिनों के भीतर दे दी जाए ।

[सं. के-12016/6/2003-डीडी 1 बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2004

S.O. 188(E).—WHEREAS certain modifications/additions which the Central Government proposed to make in the Delhi Building Bye-Laws, 1983 regarding incorporation the provisions for the protections of heritage buildings in Delhi were published in the Gazette of India as Public Notice of even number dated the 5th December, 2003 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. WHEREAS in response to the Public Notice, **No** objection and suggestion was received with regard to the proposed modifications.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Delhi Building Bye-Laws with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

"It is proposed to add clause 23 to the Building Bye-Laws, 1983 as under:

23. CONSERVATION OF HERITAGE SITES INCLUDING HERITAGE BUILDINGS, HERITAGE / PRECINCTS AND NATURAL FEATURE AREAS

Conservation of heritage sites shall include buildings, artifacts, structures, areas and precincts of historic, aesthetic, architectural, cultural or environmentally significant (heritage buildings and heritage precincts), natural feature areas of environmental significance or sites of scenic beauty.

23.1 Applicability

This regulation shall apply to heritage sites which shall include those buildings, artifacts, structures, streets, areas and precincts of historic, architectural, aesthetic, cultural or environmental value (hereinafter referred to as Listed Heritage Buildings / Listed Heritage Precincts) and those natural feature areas of environmental significance or of scenic beauty including, but not restricted to, sacred groves, hills, hillocks, water bodies (and the areas adjoining the same), open areas, wooded areas, points, walks, rides, bridle paths (hereinafter referred to as 'listed natural feature areas') which shall be listed in notification(s) to be issued by Government / identified in Master Plan.

23.1.1 Definitions

(a) *"Heritage building"* means and includes any building of one or more premises or any part thereof and/or structure and/or artifact which requires conservation and / or preservation for historical and / or architectural and / or artisanary and /or aesthetic and/or cultural and/or environmental and/or ecological purpose and includes such portion of land adjoining such building or part thereof as may be required for fencing or covering or in any manner preserving the historical and/or architectural and/or aesthetic and/or cultural value of such building.

(b) *"Heritage Precincts"* means and includes any space that require conservation and /or preservation for historical and / or architectural and/or aesthetic and/or cultural and/or environmental and/or ecological purpose. Such space may be enclosed by walls or other boundaries of a particular area or place or building or by an imaginary line drawn around it.

(c) *"Conservation"* means all the processes of looking after a place so as to retain its historical and/or architectural and/or aesthetic and/or cultural significance and includes maintenance, preservation, restoration, reconstruction and adoption or a combination of more than one of these.

(d) *"Preservation"* means and includes maintaining the fabric of a place in its existing state and retarding deterioration.

(e) *"Restoration"* means and includes returning the existing fabric of a place to a known earlier state by removing accretions or by reassembling existing components without introducing new materials.

(f) *"Reconstruction"* means and includes returning a place as nearly as possible to a known earlier state and distinguished by the introduction of materials (new or old) into the fabric. This shall not include either recreation or conjectural reconstruction.

23.2Responsibility of the Owners of Heritage Buildings

It shall be the duty of the owners of heritage buildings and buildings in heritage precincts or in heritage streets to carry out regular repairs and maintenance of the buildings. The Government, the Municipal Corporation of Delhi or the Local Bodies and Authorities concerned shall not be responsible for such repair and maintenance except for the buildings owned by the Government, the Municipal Corporation of Delhi or the other local bodies.

23.3 Restrictions on Development / Re-development / Repairs etc

(i) No development or redevelopment or engineering operation or additions / alterations, repairs, renovations including painting of the building, replacement of special features or plastering or demolition of any part thereof of the said listed buildings or listed precincts or listed natural feature areas shall be allowed except with the prior permission of Commissioner, MCD/Vice Chairman DDA/Chairman NDMC. Before granting such permission, the agency concerned shall consult the Heritage Conservation Committee to be appointed by the Government and shall act in according with the advice of the Heritage Conservation Committee.

(ii) Provided that, before granting any permission for demolition or major alterations / additions to listed buildings (or buildings within listed streets or precincts), or construction at any listed natural features, or alteration of boundaries of any listed natural feature areas, objections and suggestions from the public shall be invited and shall be considered by the Heritage Conservation Committee.

(iii) Provided that, only in exceptional cases, for reasons to be recorded in writing, the Commissioner, MCD/ Vice Chairman DDA/Chairman NDMC may refer the matter back to the Heritage Conservation Committee for reconsideration.

However, the decision of the Heritage Conservation Committee after such reconsideration shall be final and binding.

23.4Penalties

Violation of the regulations shall be punishable under the provisions regarding unauthorized development. In case of proved deliberate neglect of and/or damage to Heritage Buildings and Heritage Precincts, or if the building is allowed to be damaged or destroyed due to neglect or any other reason, in addition to penal action provided under the concerned Act, no permission to construct any new building shall be granted on the site if a Heritage Building or Building in a Heritage Precinct is damaged or pulled down without appropriate permission from Commissioner, MCD/ Vice Chairman DDA/ Chairman NDMC.

It shall be open to the Heritage Conservation Committee to consider a request for re-building/reconstruction of a Heritage Building that was unauthorizedly demolished or damaged, provided that the total built-up area in all floors put together in such new construction is not in excess of the total built-up area in all floors put together in the original Heritage Building in the same form and style in addition to other controls that may be specified.

23.5 Preparation of List of Heritage Sites including Heritage Buildings, Heritage Precincts and Listed Natural Feature Areas

The list of heritage sites including Heritage Buildings, Heritage Precincts and listed Natural Features Areas is to be prepared and supplemented by the Commissioner, MCD/ Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC on the advice of the Heritage Conservation Committee. Before being finalized, objections and suggestions of the public are to be invited and considered. The said list to which the regulation applies shall not form part of this regulation for the purpose of Building Bye-laws. The list may be supplemented from time to time by Government on receipt of proposal from the agency concerned or by Government *suo moto* provided that before the list is supplemented, objections and suggestions from the public be invited and duly considered by the Commissioner, MCD/Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC and/or Government and / or the Heritage Conservation Committee.

When a building or group of buildings or natural feature areas are listed it would automatically mean (unless otherwise indicated) that the entire property including its entire compound / plot boundary along with all the subsidiary structures and artifacts, etc. within the compound/plot boundary, etc. shall form part of list.

23.6 Alteration / Modification / Relaxation in Development Norms

On the advice of the said Heritage Conservation Committee to be appointed by the Government and for reasons to be recorded in writing, the Commissioner, MCD / Vice Chairman DDA/Chairman NDMC shall follow the procedure as per DDA Act, 1957 to alter, modify or relax the Development Control Norms prescribed in the Master Plan of Delhi, or Building Bye-laws of Delhi if required, for the conservation or preservation or retention of historic or aesthetic or cultural or architectural or environmental quality of any heritage site.

23.7 Heritage Precincts / Natural Feature Areas

In cases of streets, precincts, areas and, (where deemed necessary by the Heritage Conservation Committee) natural feature areas notified as per the provisions of this Building Bye-Laws No. 23.3 above, development permissions shall be granted in accordance with the special separate regulation prescribed for respective streets, precincts / natural feature areas which shall be framed by the Commissioner MCD/ Vice-Chairman DDA/Chairman NDMC on the advice of the Heritage Conservation Committee.

Before finalizing the special separate regulations for precincts, streets, natural features, areas, the draft of the same shall be published in the official gazette and in leading newspapers for the purpose of inviting objections and suggestions from the public. All objections and suggestions received within a period of 30 days from the date of publication in the official gazette shall be considered by the Commissioner, MCD / Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC / Heritage Conservation Committee.

After consideration of the above suggestions and objections, the agency concerned acting on the advice of the Heritage Conservation Committee shall modify (if necessary) the aforesaid draft separate regulations for streets, precincts, areas and natural features and forward the same to Government for notification.

23.8*Road Widening*

Widening of the existing roads under the Master Plan of Delhi / Zonal Development Plan or in the Layout Plan shall be carried out considering the existing heritage buildings (even if they are not included in a Heritage Precinct) or which may affect listed natural features areas.

23.9 Incentive Uses for Heritage Buildings

In cases of buildings located in non-commercial use zones included in the Heritage Conservation List, if the owner / owners agree to maintain the listed heritage building as it is in the existing state and to preserve its heritage state with due repairs and the owner / owners / lessees give a written undertaking to that effect, the owner / owners / lessees may be allowed with the approval of the Heritage Conservation Committee within permissible use zone to convert part or whole thereof of the non-commercial area within such a heritage building to commercial/office use/hotel. Provided that if the heritage building is not maintained suitably or if the heritage value of the building is spoiled in any manner, the commercial / office / hotel use shall be disallowed.

23.10 Maintaining Skyline and Architectural Harmony

After the guidelines are framed, building within heritage precincts or in the vicinity of heritage sites shall maintain the skyline in the precinct and follow the architectural style (without any high-rise or multi-storeyed development) as may be existing in the surrounding area, so as not to diminish or destroy the value and beauty of or the view from the said heritage sites. The development within the precinct or in the vicinity of heritage sites shall be in accordance with the guidelines framed by the Commissioner, MCD / Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC on the advice of the Heritage Conservation Committee or separate regulations / guidelines, if any, prescribed for respective zones by DDA/NDMC/MCD.

23.11 Restrictive Covenants

Restrictions existing as on date of this Notification imposed under covenants, terms and conditions on the leasehold plots either by Government or by Municipal Corporation of Delhi or by Delhi Development Authority or by New Delhi Municipal Council shall continue to be imposed in addition to Development Control Regulations. However, in case of any conflict with the heritage preservation interest/environmental conservation, this Heritage Regulation shall prevail.

23.12 Grading of the Listed Buildings / Listed Precincts

Listed Heritage Buildings / Listed Heritage Precincts may be graded into three categories. The definition of these and basic guidelines for development permissions are as follows:

Listing does not prevent change of ownership or usage. However, change of use of such Listed Heritage Building / Listed Precincts is not permitted without the prior approval of the Heritage Conservation Committee. Use should be in harmony with the said listed heritage site.

Grade-I	Grade-II	Grade-III
(A) Definition Heritage Grade-I comprises buildings and precincts of national or historic importance, embodying excellence in architectural style, design, technology and material usage and/or aesthetics; they may be associated with a great historic event, personality, movement or institution. They have been and are the prime landmarks of the region. All natural sites shall fall within Grade-I.	Heritage Grade-II (A&B) comprises of buildings and precincts of regional or local importance possessing special architectural or aesthetic merit, or cultural or historical significance though of a lower scale in Heritage Grade-I. They are local landmarks, which contribute to the image and identity of the region. They may be the work of master craftsmen or may be models of proportion and ornamentation or designed to suit a particular climate.	Heritage Grade-III comprises building and precincts of importance for townscape; that evoke architectural, aesthetic, or sociological interest through not as much as in Heritage Grade-II. These contribute to determine the character of the locality and can be representative of lifestyle of a particular community or region and may also be distinguished by setting, or special character of the façade and uniformity of height, width and scale.

(B) Objective: Heritage Grade-I richly deserves careful preservation.	Heritage Grade-II deserves intelligent conservation.	Heritage Grade-II deserves intelligent conservation (though on a lesser scale than Grade-II and special protection to unique features and attributes).
(C) Scope for Changes: No interventions be permitted either on exterior or interior of the heritage building or natural features unless it is necessary in the interest of strengthening and prolonging, the life of the buildings/or precincts or any part or features thereof. For this purpose, absolutely essential and minimum changes would be allowed and they must be in conformity with the original.	*Grade-II(A):* Internal changes and adaptive re-use may by and large be allowed but subject to strict scrutiny. Care would be taken to ensure the conservation of all special aspects for which it is included in Heritage Grade-II. *Grade-II(B):* In addition to the above, extension or additional building in the same plot or compound could in certain circumstances, be allowed provided that the extension / additional building is in harmony with (and does not detract from) the existing heritage building(s) or precincts especially in terms of height and façade.	Internal changes and adaptive re-use may by and large be allowed. Changes can include extensions and additional buildings in the same plot or compound. However, any changes should be such that they are in harmony with and should be such that they do not detract from the existing heritage building/precinct.
(D) Procedure: Development permission for the changes would be given on the advice of the Heritage Conservation Committee.	Development permission for the changes would be given on the advice of the Heritage Conservation Committee.	Development permission for changes would be given on the advice of the Heritage Conservation Committee.
(E) Vistas / Surrounding Development: All development in areas surrounding Heritage Grade-I shall be regulated and controlled, ensuring that it does not mar the grandeur of, or view from Heritage Grade-I.	All development in areas surrounding Heritage Grade-II shall be regulated and controlled, ensuring that it does not mar the grandeur of, or view from Heritage Grade-II.	All development in areas surrounding Heritage Grade-III shall be regulated and controlled, ensuring that it does not mar the grandeur of, or view from Heritage Grade-III.

23.13 Nothing mentioned above should be deemed to confer a right on the owner / occupier of the plot to demolish or reconstruct or make alterations to his heritage building / buildings in a heritage precinct or on a natural heritage site if in the opinion of the Heritage Conservation Committee, such demolition / reconstruction/ alteration is undesirable.

23.14 The Heritage Conservation Committee shall have the power to direct, especially in areas designated by them, that the exterior design and height of buildings should have their approval to preserve the beauty of the area.

23.15 Signs and Outdoor Display Structures / Including Street Furniture on Heritage Sites

Commissioner, MCD/ Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC on the advice of the Heritage Conservation Committee shall frame regulations or guidelines to regulate signs, outdoor display structures and street furniture on heritage sites.

23.16 Composition of Heritage Conservation Committee

The Heritage Conservation Committee shall be appointed by Government comprising of:

(i)	Additional Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	**Chairman**
(ii)	Additional Director General (Architecture), CPWD	Member
(iii)	Structural Engineer having experience of ten years in the field and membership of the Institution of Engineers, India	Member
	Architect having 10 years experience	
	A) Urban Designer	Member
	B) Conservation Architect	Member
(iv)	Environmentalist having in-depth knowledge and experience of 10 years of the subject .	Member
(v)	Historian having knowledge of the region having 10 years experience in the field	Member
(vi)	Natural historian having 10 years experience in the field	Member
(vii)	Chief Planner, Town & Country Planning Organisation	Member
(viii)	Chief Town Planner, MCD	Member
(ix)	Commissioner (Plg.), DDA	Member
(x)	Chief Architect, NDMC	Member
(xi)	Representative of DG, Archeological Survey of India	Member
(xii)	Secretary, DUAC	**Member-Secretary**

(a) The Committee shall have the powers to co-opt upto three additional members who may have related experience.

(b) The tenure of the Chairman and Members of other than Government Department / Local Bodies shall be three years.

The terms of reference of the Committee shall inter alia be:

(i) to advice the Commissioner, MCD/ Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC whether development permission to be granted under this Building Bye-Laws No.23.3 and the conditions of permission (vide BBL No. 23);

(ii) to prepare a supplementary list of heritage sites, which include buildings artifacts, structures, streets, areas, precincts of historic, aesthetic, architectural, cultural, or environmental significance and a supplementary list of natural feature areas of environmental significance, scenic beauty including but not restricted to sacred groves, hills, hillocks, water bodies (and the areas adjoining the same), open areas, wooded areas, points, walks, rides, bridle paths etc. to which this Building Bye-Law would apply.

(iii) To advise whether any relaxation, modification, alteration, or variance of any of the Building Bye-laws is called for;

(iv) To frame special regulations / guidelines for precincts and if necessary for natural feature areas to advise the Commissioner, MCD/ Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC regarding the same;

(v) To advise whether to allow commercial / office/ hotel use in the (name the areas) and when to terminate the same;

(vi) To advise the Commissioner, MCD/ Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC in the operation of this Building Bye-law to regulate or eliminate/erection of outside advertisements/bill boards/street furniture;

(vii) To recommend to the Commissioner, MCD/ Vice- Chairman DDA/ Chairman NDMC guidelines to be adopted by those private parties or public / government agencies who sponsor beautification schemes at heritage sites;

(viii) To prepare special designs and guidelines / publications for listed buildings, control of height and essential façade characteristics such as maintenance of special types of balconies and other heritage items of the buildings and to suggest suitable designs adopting appropriate materials for replacement keeping the old form intact to the extent possible.

(ix) To prepare guidelines relating to design elements and conservation principles to be adhered to and to prepare other guidelines for the purposes of this Regulation;

(x) To advise the Commissioner, MCD / Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC on any other issues as may be required from time to time during course of scrutiny of development permissions and in overall interest of heritage / conservation;

(xi) To appear before the Government either independently or through or on behalf of the Commissioner, MCD / Vice-Chairman, DDA / Chairman, NDMC in cases of Appeals under DDA/MCD/NDMC Act in cases of listed buildings / heritage buildings and listed precincts / heritage precincts and listed natural feature areas.

23.17 Implications of Listing as Heritage Buildings:

The Regulations do not amount to any blanket prevention of demolition or of changes to Heritage Buildings. The only requirement is to obtain clearance from Commissioner, MCD/ Vice- Chairman DDA/Chairman NDMC and Heritage Conservation Committee from heritage point of view.

23.18 Ownership not affected:

Sale and purchase of Heritage Buildings does not require any permission from Municipal Corporation of Delhi / Delhi Development Authority/New Delhi Municipal Council or Heritage Conservation Committee. The Regulations do not affect the ownership or usage. However, such usage should be in harmony with the said listed precincts / buildings. Care will be taken to ensure that the development permission relating to these buildings is given within 60 days."

[No. K-12016/6/2003-DD 1B]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप--नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

98-G-PCCS
27/2/04
Dy No 41 AD(MC)
3/3/04

No. K- 13011/10/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Change of land use for the District Court at Saket.

दि. वि. प्रा. / योजना एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PLG. & CO-ORDN. BRANCH
प्राप्ति सं. / DIARY No. 228
दिनांक / DATE 27-2-04

A copy of Notification dated 20th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copies to C(LD), C(LM), C(Plg), CA.

Meeting Copy

No. F1(Misc)2004/MC/DDA/28
Copy forwarded to C(LD), C(LM), C(Plg.), Chief Arch.

01/3/04 AD(MC)
DD(Plg)
1/3
05/3/04 DD(Plg)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 184] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2004

का.आ. 216(अ).— यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र का जिन कुछ उपांतरणों को करने का प्रस्ताव है उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 31 दिसंबर, 2003 को का०आ० 2(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस के तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यत: प्रस्तावित उपांतरण के बारे में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. इसलिए अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

क्र.सं.	क्षेत्र का विवरण	भू-उपयोग	
		से	में
1.	उत्तर में प्रेस इंक्लेव मार्ग, दक्षिण में 30.78 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम में जिला न्यायालय और संबद्ध कार्यालयों तथा पूर्व में डीएमआरसी आवास से घिरा सेक्टर VI, एम.बी. रोड (साकेत) का भाग	रिहायशी 112060.678 वर्ग मी०	सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक

[सं० के-13011/10/2003-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2004

S.O. 216(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary on 31st December, 2003 vide S.O. 2(E) in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Sl. No.	Description of Area	Land Use	
		From	To
1.	Part of Sector-VI, M.B. Road (Saket) Bounded by Press Enclave Marg on North, 30.78 Mt. wide Road on South, District Court and Allied Offices on West and DMRC Housing on East.	Residential 112060.678 Sq. Mt.	Public and Semi-Public

[No. K-13011/10/2003-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 13011/10/03-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Publication of corrigendum - Change of landuse of the areas adjacent to Deen Dayal Upadhyaya Park on Deen Dayal Upadhyaya Marg (Rouse Avenue) New Delhi

A copy of Corrigendum dated 17th February, 2004 to Notification dated 31st December, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 211(अ).—दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना का. आ. 1(अ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । संशोधन के क्रम सं. 2 और 3 पर दी गई विषय-वस्तु को निम्नवत पढ़ा जाए :—

क्रम संख्या	क्षेत्र का विवरण	भूमि उपयोग	
		से	में
2	उत्तर में कोटला रोड, पूर्व में संस्थागत क्षेत्र, दक्षिण में डी डी यू मार्ग तथा पश्चिम में डी डी यू पार्क से घिरी पॉकेट	(क) रिहायशी (ख) वाणिज्यिक (ग) सड़क 50,237 वर्ग मीटर	(क) सरकारी कार्यालय (ख) सरकारी कार्यालय (ग) सरकारी कार्यालय
3	उत्तर में डी डी यू मार्ग, दक्षिण में महाबतखान रोड, पश्चिम में सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल तथा पूर्व में गांधी पीस फाउंडेशन से घिरी पॉकेट 10 और 12	रिहायशी 26,355 वर्ग मीटर	सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक

[सं. के-13011/10/2003-डी डी I बी]
जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(Delhi Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 211(E).—Reference is invited to Notification S.O. 1(E) of even number dated 31st December, 2003. The contents at Sl. No. 2 and 3 of the Modification may be read as follows :—

Sl. No.	Description of Area	Land use	
		From	To
2	Pocket bounded by Kotla Road on the North, Institutional Area on East, DDU Marg on South and DDU Park on the West	a) Residential b) Commercial c) Road 50,237 sq.mtr.	(a) Govt. Office (b) Govt. Office (c) Govt. Office
3	Pocket 10 & 12, bounded by DDU Marg on North, Mahabatkhan Road on South, Sr. Sec. School on West and Gandhi Peace Foundation on the East.	Residential 26,355 sq. mtr.	Public and Semi-Public

[No. K-13011/10/2003-DDIB]
J. S. DUA, Under Secy.

548 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Office of the Pr. Commr.-cum-Secretary)

No. F.1(Misc.)2004/MC/DDA/ 3 / Dated: 5th March, 2004

Sub: **Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.**

I am directed to enclose herewith a copy of letter No. K-12016/4/2003/DD-IB dated 26th February 2004 alongwith a copy of Notification dated 17.2.2004 received from Shri S Mukherjee, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Government of India, on the subject cited above for information and necessary action.

05/3/04
[S C TUTEJA]
Deputy Director [P&C]

Copy to:

1. Commissioner [Planning]
2. Addl. Commissioner [Planning]
3. Chief Architect

Encl: As above.

Copy also to:

1. Vice Chairman]
2. Engineer Member] for kind information.
3. Finance Member]

05/3/04
Deputy Director [P&C]

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Office of the Pr. Commr.-cum-Secretary)

No. F.1(Misc.)2004/MC/DDA/ Dated: 5th March, 2004

Sub: **Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.**

I am directed to enclose herewith a copy of letter No. K-12016/4/2003/DD-IB dated 26th February 2004 alongwith a copy of Notification dated 17.2.2004 received from Shri S Mukherjee, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Government of India, on the subject cited above for information and necessary action.

[S C TUTEJA]
Deputy Director [P&C]

Copy to:

1. Commissioner [Planning]
2. Addl. Commissioner [Planning]
3. Chief Architect

Encl: As above.

Copy also to:

1. Vice Chairman]
2. Engineer Member] for kind information.
3. Finance Member]

Deputy Director [P&C]

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Office of the Pr. Commr.-cum-Secretary)

No. F.1(Misc.)2004/MC/DDA/ Dated: 5th March, 2004

Sub: **Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.**

I am directed to enclose herewith a copy of letter No. K-12016/4/2003/DD-IB dated 26th February 2004 alongwith a copy of Notification dated 17.2.2004 received from Shri S Mukherjee, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Government of India, on the subject cited above for information and necessary action.

[S C TUTEJA]
Deputy Director [P&C]

Copy to:

1. Commissioner [Planning]
2. Addl. Commissioner [Planning]
3. Chief Architect

Encl: As above.

Copy also to:

1. Vice Chairman]
2. Engineer Member] for kind information.
3. Finance Member]

Deputy Director [P&C]

No. K- 12016/4/2003-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 26th February, 2004

Subject: Amendment of Building Bye-laws, 1983 – Increasing validity period of building permit to five years.

A copy of Notification dated 17th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
   The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यत: भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यत: एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यत: केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

"भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुन: वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अध्यधीन होगा"।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

"The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area".

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K- 13011/10/03-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 20th May, 2004

Subject: **Publication of corrigendum - Change of landuse of the areas adjacent to Deen Dayal Upadhyaya Park on Deen Dayal Upadhyaya Marg (Rouse Avenue) New Delhi**

A copy of Corrigendum dated 14th May, 2004 to Notification dated 19th February, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Director (MP), DDA, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi
2. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
4. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
5. Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
6. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
9. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copies to Commr(Plg), CA, CE(HQ) 21/5/04

AD(MC)

1. Commr (Plg)
2. Chief Architect
3. CE (HQ).

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 2004/वैशाख 24, 1926
No. 442] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 2004/VAISAKHA 24, 1926

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 13 मई, 2004

का.आ. 574(अ).—अधिसूचना सं. का.आ. 216(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2004 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त अधिसूचना के कालम "क्षेत्र का विवरण" के अन्तर्गत प्रावधानों को निम्नवत पढ़ा जाए।

क्षेत्र का विवरण

"उत्तर में प्रेस एन्कलेव मार्ग, दक्षिण में 30.78 मीटर चौड़ी सड़क (एनडीएमसी स्टाफ क्वार्टरों के अलावा), पश्चिम में जिला न्यायालय और सम्बद्ध कार्यालय, पूर्व में 18 मीटर चौड़ी सड़क (डीएमआरसी आवास के अलावा) से घिरा सेक्टर VI, एम. बी. रोड (साकेत) का भाग"

[सं. के-13011/10/2003-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(Delhi Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th May, 2004

S.O. 574(E).—Reference is invited to Notification No. S.O. 216(E) dated 19th February, 2004. The provisions under the column "Description of Area" of the said Notification may be read as under :—

Description of Area

"Part of Sector VI, M.B. Road (Saket) bounded by Press Enclave Marg on North, 30.78 mts. wide Road on South (excluding NDMC staff quarters) District Court and Allied Offices on West, 18 mts. wide Road on East (excluding DMRC Housing)"

[No. K-13011/10/2003-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

1545 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No.K-11011/28/2002-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi -110 011.
Dated the 14th July, 2004.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Laying of Amendments to Recruitment Regulations for various posts in Delhi Development Authority.**

The undersigned is directed to state that as per the provisions laid down under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), every Rule/ Regulation made under the said Act is to be laid on the Table of both Houses of Parliament.

2. Accordingly, one copy each of the Gazette Notifications dated 8.12.2003 (GSR No.932) and its corrigendum dated 20.1.2004 (GSR No.57) (both, Hindi and English versions) amending the Recruitment Regulations for various posts in DDA duly authenticated by the Minister for Urban Development are sent herewith, together with the prescribed proforma and the requisite number of copies in Hindi/English (41 copies each) for laying the same on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha.

Encl. : As above.

Sd/-
Parmjit Singh
Desk Officer(DDIA)
Telefax:23017478

To

1. The Lok Sabha Sectt., (Distribution Branch),
   Parliament House Annexe, New Delhi.

2. The Rajya Sabha Sectt. (Table Office),
   529, Parliament House Annexe, New Delhi.

Copy for information to:

1. PS to UDM.
2. Under Secretary (Parliament), Ministry of UD&PA, New Delhi.
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Desk Officer

PROFORMA TO BE ATTACHED TO THE O.M. FORWARDING PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF RAJYA SABHA/LOK SABHA.

1. Brief purport of the matter the notification covers or papers to be laid on the Table.	Amendments to Recruitment Regulations for the posts of Stenographers, Senior Stenographers, Lower Division Clerk–cum-typist (Hindi/English), Upper Division Clerk, Assistants, Welfare/Personnel Inspector, Manager (Sports), Assistant Manager (Sports), Game Supervisor & Games Attendant in Delhi Development Authority (DDA) and corrigendum thereto.
2. Statutory or other requirement under which the paper is to be laid on the Table. i) in the case of Central Govt. Notification name of the Act and section which provides for laying should be clearly stated. ii) in the case of State Govt. Notification the laying provision in the State Act should be reproduced.	Under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957, every rule/regulation made under this Act is to be laid before each House of Parliament for a total period of 30 days which may be comprised in one or two sessions or in two or more successive sessions.
3.Whether published in the Gazette and if so, i) GSR/S.O./S.R.O. number of notification published in the Gazette. ii) Date and part section of the Gazette. * Whether subject to modification by the House. * Period specified in the principal Act which it is required to be laid.	Yes. i)GSR 932 (E) ii) GSR 57 (E) i) 8th December, 2003, Part II Section-3, Sub-Section (i). ii) 20th January, 2004, Part II Section 3, Sub-Section (i). Yes. 30 days.
* Whether it has been previously laid on the Table of the Rajya Sabha and if so, on what date. * Whether English and Hindi versions are being laid together? If not the date on which the English versions was laid. * Date on which proposed to be laid on the Table.	No. Yes. On any day allotted to this Ministry.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2004/माघ 1, 1925
No. 27] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2004/MAGHA 1, 1925

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-3)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2004

सा. का. नि. 57(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड-(i), दिनांक 8 दिसम्बर, 2003, में पृष्ठ 13 पर प्रकाशित प्रबन्धक (खेल) के भर्ती विनियम की अधिसूचना सा.का.नि. 932(अ) दिनांक 8 दिसम्बर, 2003, में कालम 11 (3) में **"किसी अन्य विभाग से"** के स्थान पर **"किसी अन्य विभाग से निदेशक स्तर का प्रतिनिधि"** तथा उसी अधिसूचना में पृष्ठ 16 पर सहायक प्रबंधक (खेल) के भर्ती विनियम में कालम 3 **"वर्गीकरण : समूह 'ख' (अराजपत्रित)"** के स्थान पर **"वर्गीकरण : समूह 'ग' (अराजपत्रित)"** पढ़ें।

[सं. एफ-6(15)2000/पी.बी. III/88]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

222 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA (EXTRAORDINARY)

392-G-PCCS
23/9/04.

No.K-11011/21/2004-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)
*****

New Delhi, the 22nd September, 2004.

NOTIFICATION

G.S.O. No. Pursuant to their election by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Central Government in accordance with the provisions of sub-section (i), read with clause (f) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), hereby nominates Shri Jile Singh Chauhan, Shri Mahabal Mishra & Shri Mange Ram Garg, MLAs as Members of the Delhi Development Authority with immediate effect.

Sd/-
(Parmjit Singh)
Desk Officer

To

148-AD/MC
24/9/04

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

Copy forwarded to

1. Secretary to the Lt. Governor, Delhi.
2. Shri Jile Singh Chauhan, MLA, 1908, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi
3. Shri Mahabal Mishra , MLA, RZ-D1/41, Vinodpuri, Vijay Encl., New Delhi.
4. Shri Mange Ram Garg, MLA, B1/64, Ashok Vihar, Ph.II, Delhi.
5. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi.
6. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, New Delhi.
7. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Secretary, Delhi Legislative Assembly, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi.
10. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi.
11. Chief Planner, TCPO, Vikas Bhavan, New Delhi.
12. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.

Desk Officer

Copy also forwarded to PS to UDM, Sr. PPS to Secretary (UD), PS to Joint Secretary (DL), PS to Director (DD).

Desk Officer

24/9

DD(Plg)

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ (असाधारण)

सं0 के-11011/20/2004-डी डी आई ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 सितम्बर, 2004

अधिसूचना

जी एस ओ सं0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निर्वाचित होने पर केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61), की धारा 3 की उप धारा (3) के खण्ड (च) के साथ पठित उप धारा (I) के प्रावधानों के अनुसार श्री जिले सिंह चौहान, विधायक, श्री महाबल मिश्र, विधायक तथा श्री मांगे राम गर्ग, विधायक को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है ।

परमजीत सिंह

(परमजीत सिंह)
डेस्क अधिकारी

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

सूचनार्थ प्रति :-

1. उप राज्यपाल, दिल्ली के सचिव ।
2. श्री जिले सिंह चौहान, विधायक, 1908, आउटरमलाइन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली ।
3. श्री महाबल मिश्र, विधायक, आर जेड-डी 1/41, विनोदपुरी, विजय इन्क्लेव, नई दिल्ली ।
4. श्री मांगे राम गर्ग, विधायक, बी 1/64, अशोक विहार, फेज-IX, नई दिल्ली ।
5. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई एन ए कालोनी, नई दिल्ली ।
6. प्रधान आयुक्त-सह-सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ।
7. मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।

8. सचिव, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
9. इंजीनियर सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई एन ए कालोनी, नई दिल्ली ।
10. वित्त सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आई एन ए कालोनी, नई दिल्ली ।
11. मुख्य नियोजक, टी सी पी ओ, विकास सदन, नई दिल्ली ।
12. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हॉल, दिल्ली ।

परमजीत सिंह
डेस्क अधिकारी

प्रतिलिपि शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव, सचिव (श0वि0) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डीएल) के निजी सचिव, निदेशक (डीडी) के निजी सचिव को भी अग्रेषित है ।

परमजीत सिंह
डेस्क अधिकारी

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2004/आश्विन 2, 1926
No. 813] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2004/ASVINA 2, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2004

का.आ. 1037(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निर्वाचित होने पर केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61), की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री जिले सिंह चौहान, विधायक, श्री महाबल मिश्र, विधायक तथा श्री मांगे राम गर्ग, विधायक को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं. के-11011/21/2004-डीडीआईए]

परमजीत सिंह, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2004

S.O. 1037 (E).—Pursuant to their election by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Central Government in accordance with the provisions of Sub-section (i), read with caluse (f) of Sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), hereby nominates Shri Jile Singh Chauhan, Shri Mahabal Mishra and Shri Mange Ram Garg, MLAs as Members of the Delhi Development Authority with immediate effect.

[No. K-11011/21/2004-DDIA]

PARMJIT SINGH, Desk Officer

2894 GI/2004

M/o U.D.
Delhi Division

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Copy forwarded to:
The Principal Commissioner cum Secretary, DDA.

29-9-04
Desk Officer

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2004/आश्विन 2, 1926
No. 813] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2004/ASVINA 2, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2004

का.आ. 1037(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निर्वाचित होने पर केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61), की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री जिले सिंह चौहान, विधायक, श्री महाबल मिश्र, विधायक तथा श्री मांगे राम गर्ग, विधायक को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं. के-11011/21/2004-डीडीआईए]

परमजीत सिंह, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2004

S.O. 1037 (E).—Pursuant to their election by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Central Government in accordance with the provisions of Sub-section (i), read with caluse (f) of Sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), hereby nominates Shri Jile Singh Chauhan, Shri Mahabal Mishra and Shri Mange Ram Garg, MLAs as Members of the Delhi Development Authority with immediate effect.

[No. K-11011/21/2004-DDIA]

PARMJIT SINGH, Desk Officer

2894 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-20013/13/99-DD-IB(part)
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29th September, 2004

Subject: Government Notification(Public Notice) No. S.O.1016(E) dated 20.9.2004 regarding change of land use at the MRTS site

A copy of Public Notice mentioned above published in the Gazette of India Extraordinary, is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Secretary, Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi
2. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
3. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
5. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
6. The Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi..
7. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, NDMC, New Delhi.
9. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
10. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
11. The Chief Architect – I, CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi
12. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 795] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 2004/भाद्र 29, 1926

No. 795] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 2004/BHADRA 29, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2004

का.आ. 1016(अ).—दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन/उपांतरण, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हों, तो उन्हें इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर लिखित रूप में अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है। आपत्ति अथवा सुझाव भेजने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी भिजवाएं।

उपांतरण :

वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली-110029 सहित सफदरजंग अस्पताल के संबंध में ग्राउंड कवरेज तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर) निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाने का प्रस्ताव है :—

		मौजूदा	प्रस्तावित उपांतरण
(i)	ग्राउंड कवरेज	25%	35%
(ii)	फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर)	100	150

[सं. के-20013/13/99-डीडीबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th September, 2004

S.O. 1016(E).—The following amendments/modifications which the Central Government propose to make in the Master Plan for Delhi, 2001 are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Under Secretary, Delhi Division, Ministry of Urban Development, Nirman Bhavan, New Delhi-110 011 within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification :

It is proposed to modify the ground coverage and Floor Area Ratio (FAR) in respect of Safdarjang Hospital, including Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi-110 029 as under :—

	Existing	Proposed Modification
(i) Ground Coverage	25%	35%
(ii) Floor Area Ratio	100	150

[No. K-20013/13/99-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-20013/13/99-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 15th Dec., 2004

Subject: Gazette Notification No. 1322 S.O.(E) dated 2.12.2004 regarding revision of Ground Coverage and FAR for Safdarjang Hospital including Vardhaman Mahavir Medical College

A copy of Public Notice mentioned above published in the Gazette of India Extraordinary, is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Secretary(BT), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi.
2. Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi
3. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
4. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
6. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
7. The Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
12. The Chief Architect – I, CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi
13. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Delhi Development Authority
Meeting Cell

No. F 1(Misc.)2000/MC/D.D.A/ 120 Dated 4/1/05

Copy forwarded to:-

1. Finance Member, DDA
2. Engineer Member, DDA
3. Commissioner (Planning) DDA.
4. Chief Architect, DDA
5. Pr. Commissioner, DDA.
6. Commissioner (L.D), DDA

4.1.05
Assistant Director
Meeting Cell

O/C 3.1.05.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1028] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2004/अग्रहायण 12, 1926
No. 1028] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2004/AGRAHAYANA 12, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2004

का०आ० 1322(अ).—यत: वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सहित सफदरजंग अस्पताल के संबंध में ग्राउंड कवरेज तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर) के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 20 सितम्बर, 2004 की राजपत्र की अधिसूचना सं० का०आ० 1016 (अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: सार्वजनिक सूचना के उत्तर में प्रस्तावित संशोधन के बारे में केवल एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ और केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपांतरण :

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली-110 029 सहित सफदरजंग अस्पताल के संबंध में ग्राउंड कवरेज तथा फर्शी क्षेत्र (एफएआर) निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किये जाते हैं :—

	मौजूदा	प्रस्तावित उपांतरण
(i) ग्राउंड कवरेज	25%	35%
(ii) फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर)	100	150

[सं० के-20013/13/99-डीडीआईबी]

एस० मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2004

S. O. 1322 (E).—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 in the matter of Ground Coverage and Floor Area Ratio for Safdarjang Hospital, including Vardhaman Mahavir Medical College were published as a Public Notice vide Gazette Notification No. S. O. 1016 (E) dated 20th September, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) for inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas only one objection/suggestion had been received with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The Ground Coverage and Floor Area Ratio (FAR) permissible in respect of Safdarjang Hospital, including Vardhman Mahavir Medical College, New Delhi-110 029 stands modified as under :—

	Existing	Modified
(i) Ground Coverage	25%	35%
(ii) Floor Area Ratio	100	150

[No. K-20013/13/99-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-20013/13/99-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 15th Dec., 2004

Subject: Gazette Notification No. 1322 S.O.(E) dated 2.12.2004 regarding revision of Ground Coverage and FAR for Safdarjang Hospital including Vardhaman Mahavir Medical College

A copy of Public Notice mentioned above published in the Gazette of India Extraordinary, is sent herewith for information and necessary action.

(S.Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23016681

Copy to:

1. The Joint Secretary(BT), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi.
2. Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi
3. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
4. The Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
6. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
7. The Engineer in Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The DG(W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi.
12. The Chief Architect – I, CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi
13. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1028] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2004/अग्रहायण 12, 1926

No. 1028] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2004/AGRAHAYANA 12, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2004

का०आ० 1322(अ).—यत: वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सहित सफदरजंग अस्पताल के संबंध में ग्राउंड कवरेज तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर) के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 20 सितम्बर, 2004 की राजपत्र की अधिसूचना सं० का०आ० 1016 (अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: सार्वजनिक सूचना के उत्तर में प्रस्तावित संशोधन के बारे में केवल एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ और केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपांतरण :

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली-110 029 सहित सफदरजंग अस्पताल के संबंध में ग्राउंड कवरेज तथा फर्शी क्षेत्र (एफएआर) निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किये जाते हैं :—

	मौजूदा	प्रस्तावित उपांतरण
(i) ग्राउंड कवरेज	25%	35%
(ii) फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर)	100	150

[सं० के-20013/13/99-डीडीआईबी]

एस० मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2004

S. O. 1322 (E).—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 in the matter of Ground Coverage and Floor Area Ratio for Safdarjang Hospital, including Vardhaman Mahavir Medical College were published as a Public Notice vide Gazette Notification No. S. O. 1016 (E) dated 20th September, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) for inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas only one objection/suggestion had been received with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The Ground Coverage and Floor Area Ratio (FAR) permissible in respect of Safdarjang Hospital, including Vardhman Mahavir Medical College, New Delhi-110 029 stands modified as under :—

	Existing	Modified
(i) Ground Coverage	25%	35%
(ii) Floor Area Ratio	100	150

[No. K-20013/13/99-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. J-13036/1/2004-DDVA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)
*****

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 17th December, 2004.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Laying of Amendments to Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981.

****

The undersigned is directed to state that as per the provisions laid down under Secton 58 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Gazette Notification containing the Amendment of Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 is required to be laid on the Table of both the Houses of Parliament.

2. Accordingly, a copy of the notification (bilingual) duly authenticated by the Minister for Urban Development are sent herewith together with the prescribed proforma and the requisite number of copies (41 copies) for laying the same on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha.

(**Prem Kumar**)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2301 7478

Encl: As above.

To

1. The Lok Sabha Secretariat
(Distribution Branch),
Parliament House Annexe,
New Delhi.

2. The Rajya Sabha Secretariat
(Committee Sec.I),
529, Parliament House Annexe,
New Delhi.

Copy for information to:

1. PS to UDM
2. Under Secretary (Parliament), MoUD, New Delhi.
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA,Vikas Sadan, INA, New Delhi-110 023.

No. F 2(2) 2004/MC/DDA/118 dt. 3-1-05 ~~3-1-04~~

Copy to :-

1. Commissioner (L.D.)
2. Commissioner (L.M.)

03/1/05
Dy. Director (M.C.)

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2004/अग्रहायण 18, 1926

No. 542] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2004/AGRAHAYANA 18, 1926

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 801(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का क्रमांक 61) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से एतद्द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981, जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है के नियम 4 के उप-नियम (2) में "अस्पतालों अथवा डिस्पेंसरियों" शब्दों के लिए "अस्पतालों, डिस्पेंसरियों अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाओं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम के नियम 5 में निहित स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण :**

इस नियम के प्रयोजनार्थ "कालेजों", "विश्वविद्यालयों" तथा "अस्पतालों" नामक अभिव्यक्तियों में नियम 4 के उप-नियम (2) में यथा-उल्लिखित किसी कम्पनी, फर्म अथवा ट्रस्ट, जैसा भी मामला हो, द्वारा संस्थापित उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं अथवा अस्पताल अथवा विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।"

4. उक्त नियम के नियम 8 में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्द के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 20 में,—

(i) खण्ड (ख) में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्द के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ङ) में निहित परन्तुक में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्दों के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-13036/1/2004-डीडीवीए]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 26 सितम्बर, 1981 को सं. सा.का.नि. 872 के तहत प्रकाशित किए गए थे, जो दिनांक 27-1-1989 के सं. सा.का.नि. 97, दिनांक 11-11-1991 के सं. सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 5-7-2002 के सं. सा.का.नि. 486(अ) तथा अंत में दिनांक 3-12-2002 के सं. सा.का.नि. 806(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2004

G.S.R. 801(E).—In exercise of the powers conferred by Section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authrity (Disposal of Developed Nazual Land) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub rule (2) of rule 4 of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazual Land) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "hospitals or dispensaries", the words, "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes", shall be substituted.

3. In rule 5 of the said rules, for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation :—For the purposes of this rule the expression "colleges", "universities" and "hospitals" do not include higher/technical education institutes or hospitals or universities established by a company, firm or trust, as the case may be as referred to in sub-rule (2) of rule 4."

4. In rule 8 of the said rules, for the words "hospital or dispensary" the words, "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" shall be substituted.

5. In rule 20 of the said rules,—

(i) in clause (b), for the words "hospital or dispensary", the words "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" shall be substituted;

(ii) in clause (e), in the proviso, for the words "hospital or dispensary" the words "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" made shall be substituted.

[F. No. J-13036/1/2004/DDVA]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 872, dated the 26th September, 1981, amended *vide* number G.S.R. 97 dated the 27th January, 1989, number G.S.R. 677(E), dated the 11th November, 1991, number G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002 and lastly amended *vide* number G.S.R. 806(E), dated the 3rd December, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. J-13036/1/2004-DDVA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)
*****

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 17th December, 2004.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Laying of Amendments to Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981.

****

The undersigned is directed to state that as per the provisions laid down under Secton 58 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Gazette Notification containing the Amendment of Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 is required to be laid on the Table of both the Houses of Parliament.

2. Accordingly, a copy of the notification (bilingual) duly authenticated by the Minister for Urban Development are sent herewith together with the prescribed proforma and the requisite number of copies (41 copies) for laying the same on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha.

(**Prem Kumar**)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2301 7478

Encl: As above.

To

1. The Lok Sabha Secretariat
(Distribution Branch),
Parliament House Annexe,
New Delhi.

2. The Rajya Sabha Secretariat
(Committee Sec.I),
529, Parliament House Annexe,
New Delhi.

Copy for information to:

1. PS to UDM
2. Under Secretary (Parliament), MoUD, New Delhi.
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA,Vikas Sadan, INA, New Delhi-110 023.

No. F 2(2) 2004/MC/DDA dt.

Copy to :-

1. Commissioner (L.D)
2. Commissioner (L.M)

Dy. Director (M.C)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2004/अग्रहायण 18, 1926

No. 542] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2004/AGRAHAYANA 18, 1926

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 801(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का क्रमांक 61) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से एतद्द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981, जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है के नियम 4 के उप-नियम (2) में "अस्पतालों अथवा डिस्पेंसरियों" शब्दों के लिए "अस्पतालों, डिस्पेंसरियों अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाओं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम के नियम 5 में निहित स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजनार्थ "कालेजों", "विश्वविद्यालयों" तथा "अस्पतालों" नामक अभिव्यक्तियों में नियम 4 के उप-नियम (2) में यथा-उल्लिखित किसी कम्पनी, फर्म अथवा ट्रस्ट, जैसा भी मामला हो, द्वारा संस्थापित उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं अथवा अस्पताल अथवा विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।"

4. उक्त नियम के नियम 8 में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्द के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 20 में,—

(i) खण्ड (ख) में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्द के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ङ) में निहित परन्तुक में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्दों के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-13036/1/2004-डीडीवीए]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 26 सितम्बर, 1981 को सं. सा.का.नि. 872 के तहत प्रकाशित किए गए थे, जो दिनांक 27-1-1989 के सं. सा.का.नि. 97, दिनांक 11-11-1991 के सं. सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 5-7-2002 के सं. सा.का.नि. 486(अ) तथा अंत में दिनांक 3-12-2002 के सं. सा.का.नि. 806(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2004

G.S.R. 801(E).—In exercise of the powers conferred by Section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authrity (Disposal of Developed Nazual Land) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub rule (2) of rule 4 of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazual Land) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "hospitals or dispensaries", the words, "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes", shall be substituted.

3. In rule 5 of the said rules, for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely :—

"**Explanation** :—For the purposes of this rule the expression "colleges", "universities" and "hospitals" do not include higher/technical education institutes or hospitals or universities established by a company, firm or trust, as the case may be as referred to in sub-rule (2) of rule 4."

4. In rule 8 of the said rules, for the words "hospital or dispensary" the words, "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" shall be substituted.

5. In rule 20 of the said rules,—

(i) in clause (b), for the words "hospital or dispensary", the words "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" shall be substituted;

(ii) in clause (e), in the proviso, for the words "hospital or dispensary" the words "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" made shall be substituted.

[F. No. J-13036/1/2004/DDVA]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 872, dated the 26th September, 1981, amended *vide* number G.S.R. 97 dated the 27th January, 1989, number G.S.R. 677(E), dated the 11th November, 1991, number G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002 and lastly amended *vide* number G.S.R. 806(E), dated the 3rd December, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.